[श्री शांति त्यागी]

की पिराई शुरू हो जायेगी। गन्ने का उत्पादन लागत बढ़ गया है। मान्यवर, आप भी ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां गन्ना बड़ी मात्रा में पैदा होता है। मान्यवर, खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। मैं एक मिसाल यहां पर देना चाहता हूं। जब गन्ना खेत में बड़ा हो जाता है तो उसको बांधा जाता है। बहुत से भाई नहीं जानते हैं कि वह गिरे नहीं इसलिये उनके पेड़ों को मिलाकर बांधते हैं। तो एक कच्चा बीघा के गन्ने को बांधने के लिये अगर किसी मजदूर को रखें तो वह 30 रुपये गन्ना बांधने का चार्ज करता है। जब कि कुछ दिन पहले यह मजदूरी सिर्फ 5 रुपये थी। इसमें 25 रुपये का इजाफा हो गया है। इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि किसानों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को कम से कम 32 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत की घोषणा इस सदन में करें।

अंत में मैं गन्ने की दरों में तबदीली के साथ साथ सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि चीनी मिलों को लगाने के संबंध में केंद्रीय सरकार की जो नीति है वह बहुत सख्त है। उसको थोड़ा उदार करें और जहां चीनी मिल खोलने की जरूरत है, जहां पर इसके लिये किसानों की मांग है और जहां गन्ना उपलब्ध है वहां चीनी मिलों को खोलने के लिये सरकार लाइसेंस दे। यह मांग भी मेरी आपके माध्यम से सरकार से है।

अंत में मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कम से कम 32 रुपये गन्ने का मूल्य निश्चित किया जाए और चीनी मिलों के खोलने के बारे में उदार नीति सरकार बनाये यह मेरा आग्रह है। मैं आशा करता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि इस वक्त जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे है, इस सदन में बैठे हैं, जहां तक मैं समझता हूं सब किसान हैं और कोई भी गैर किसान मेंबर यहां पर नहीं है। इसलिये वे एक राय से इस सदन के माध्यम से यह मांग करें कि गन्ने का मूल्य कम से कम 32 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए और चीनी मिलों को खोलने के बारे मे सरकार अपनी नीति को उदार बनाये।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : मै शान्ति त्यागी का समर्थन करता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) मैं मांग करता हूं कि

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): After this, there are two more special mentions, and after that is over, Shri Bhajan Lal will make a statement.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): इसका हम समर्थन करना चाहेंगे। यह गन्ने का मसला है और इस संबंध में त्यागी जी ने जो कहा है हम उससे बिल्कुल सहमत हैं ताकि किसानों का एक्सप्लाइटेशन न हो। हम सब इसका समर्थन करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : हो गया है पूरे सदन का समर्थन।

Need for Financial Assistance to Gujarat

श्री छोटूभाई सुखाभाई पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से गुजरात के आर्थिक जीवन का जो महत्वपूर्ण मसला है वह उठा रहा हूं। गुजरात का समुद्र का किनारा करीबन 16 सौ किलोमीटर है और सारे किनारे पर, गुजरात के कोस्टल एरिया में बस्तियां बसी हुई हैं। महोदय, इसके कारण सलाइन वाटर कल्टीवेशन की लैंड को खराब कर रहा है। जिससे हमारे गुजरात की करीबन 10 हजार एकड़ जमीन सलाइन वाटर से खराब हो गई है। कई गांवों में इसका बहुत बुरा असर हुआ है। इसके कारण कई गांवों को खाली करवाया है। गुजरात सरकार ने उसके लिये रेक्लेमेशन बोर्ड भी बनवाया है और शिवराज कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। फिर भी गुजरात के लिये यह प्राबलम बहुत बड़ी है। वहां पर जो सलाइन वाटर की प्राबलम है गुजरात सरकार अपने आप इससे नहीं निपट सकती। इसलिये मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करता हूं कि गुजरात की सरकार को इस प्राबलम से निपटने के लिये ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए। हमारे यहां कई परियोजनायें हैं।

नर्मदा की जो पाइपलाइन परियोजना एन०आर०आई० की है जो प्लानिंग कमीशन को प्रस्तुत की गई है उसको जल्दी से जल्दी मंजूर कराया जाए और इस नर्मदा परियोजना के इम्पलीमेंटेशन के लिए एक क्रैश प्रोग्राम बनाया जाए वरन् सौराष्ट्र के सुरेन्द्र नगर, जूनागढ़ तथा जामनगर के जिलों की जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है इस परियोजना के पूरा होने के इन जिलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकेगा। इसके इलावा हमारे यहां की 29 मध्यम कक्षा की परियोजनाएं हैं, 6 मोटी परियोजनाएं हैं, इनका इम्पलीमेंटेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए तो मुझ को यह लगता है कि इससे हम बड़े बड़े रिजर्वायर 250 लम्बाई, 150 चौड़ाई तथा 10 मीटर गहराई के बना सकेंगे। यह रिजर्वायर समुद्र के किनारे बनाए जाएंगे जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे यहां सलाइन वाटर बहुत ज्यादा बन रहा है इससे हम उसके बारे में कुछ कर सकेंगे। टेक्नोलोजी मिशन जो अभी काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत बड़ा काम है इसलिए टेक्नोलोजी मिशन को वहां ज्यादा काम करना चाहिये। मैं आपको एक एग्जेम्पल दे रहा हूं डांग जिले में 100 से 100 इंच पानी बरसता है लेकिन डांग और धरमपुर के एरिया में गर्मियों में टैंकरों के द्वारा पानी भेजना पड़ता है। यह सिचुयेशन वहा पर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि रिक्लेमेशन के बारे में तथा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिये। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फ्लोराइड-युक्त वाटर है और गिनीवोर्म वाटर बहुत ज्यादा है। मैं यह कह रहा हूं कि 6 स्टेट्स में यह गिनी-वोर्म वाटर है, 13 स्टेट्स में फ्लोराइड वाटर है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ढाई करोड़ लोग फ्लोराइड वाटर की समस्या से पीड़ित हैं और 14 स्टेट्स में आइरन वाटर है और 14 स्टेट्स में सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर से 14 स्टेट्स प्रभावित है जो कोस्टल एरियाज की स्टेट्स हैं। मेरी आपसे विनती है कि सलाइन वाटर की समस्या के कारण हमारे यहां की जमीन

[श्री छोटू भाई सुखा भाई पटेल]

बहुत बिगड़ गई है, वहां का पानी स्लाइन हो गया है इसलिए इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मदद करे और इसके लिए मेरी यह मांग है कि कोस्टल एरिया सब-प्लान बनाई जाए ताकि यह समस्या हल हो सके और इम्पलीमेंटेशन के लिए फ्रेश प्रोग्राम बनाए जाएं तो यह गुजरात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI RAOOF VALIULLAH (GUJARAT) : Mr. Vice-Chairman, Sir, this problem of salinity has been raised again and again in this House over the last five years, but no concrete steps have been taken either by the State Government or by the Central Government. Fortunately, with the starting of the technology mission, for the first time, the problem of salinity and brackishness is being tackled on a war footing. Rs. 5 crores have been earmarked. As my hon. colleague pointed out, the problem of salinity in the entire coastal area of Gujarat should be tackled on a very urgent basis. I would, therefore, request the Government, particularly, the hon. Minister of Rural Development, to look into this.

Stoppage of Steamer Service by S.C.I in Goa

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of the Government to the plight of the people residing on the Konkan coast due to the stoppage of steamer service by the S.C.I.

Since the liberation of Goa and even before that, as you must be well aware, Goa was linked with Bombay and other coastal districts of Maharashtra with steamer service catering to the needs of the people on the Konkan coast. The steamer service did not only help passenger service but also was useful for the transport of perishable farm and other livestock products to the cities of Bombay and Panjim. It was the most convenient and cheap mode of transport for the old and the sick who wanted to avail of medical treatment in the cities. But to the utter surprise of the people of the Konkan coast, the steamer service was withdrawn on the plea that there was need to put the steamer service to better use elsewhere for a greater national cause. As such, the people of the area did not object to it. Now, it appears from the Government's utterances that the steamer service may not be continued under the pretext that it is running at a loss.

Sir, the main purpose of any public sector transport undertaking is not of commercial nature, to make profit, but to cater to the needs of the travelling public. It should be service-oriented. It is hoped that the Central Government will cooperate with the Governments of Maharashtra and Goa to resume this service during this season at least to alleviate the problems faced by these people.